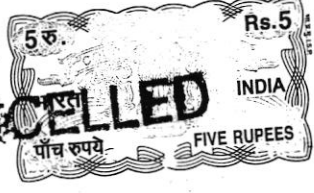
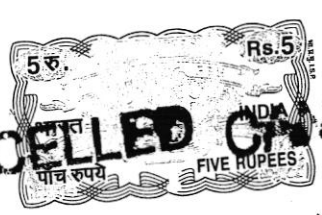


43



समक्ष न्यायालय श्रीमान् म०प्र० भू-राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर,

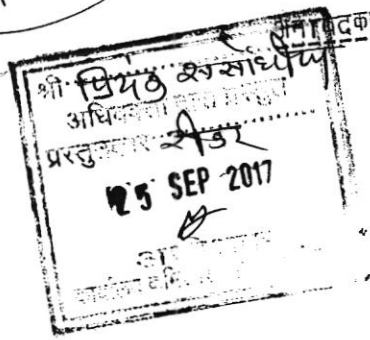
सर्किट बैच कैम्प जबलपुर म०प्र०

गिगराजी/छिन्दवाड़ा/भू-रा/2017/4315 /2017
रिवीजन प्रकरण क्रमांक :-

रिवीजनकर्ता :- गजानन पिता राजाराम खोडनकर आयु लगभग 70 वर्ष
निवासी लोधीखेड़ा, तहसील सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा म०प्र०

विरुद्ध

429



संनिपादकगण :-

- 11 श्रीमति गंगुबाई पति स्व. श्री डोमा खोडनकर,
- 12 शालिकराम पिता स्व. श्री डोमा खोडनकर
- 13 पांडुरंग पिता स्व. श्री डोमा खोडनकर
- 14 यमुना बाई विधवा भाऊराव बाल्माण्डे,
- 15 मंदाबाई पति विष्णु टेकाडे .
- 16 नेमीचंद पिता डोमा खोडनकर
सभी निवासी- लोधीखेड़ा तहसील सौंसर,
जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.
- 17 कुसुमबाई पति विष्णु राहते,
निवासी- बिड़गांव, पोस्ट केलोद, तहसील सावनेर,
जिला नागपुर महाराष्ट्र

रिवीजन अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959.

रिवीजनकर्ता, माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड के समक्ष माननीय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा द्वितीय राजस्व अपील प्र० क्रं० 588/ए-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27.9.16 सलग्न दस्तावेज प्रदर्श पी-1। उद्भूत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सौंसर जिला-छिन्दवाड़ा म०प्र० के रा० प्र० क्रं० 71/अ-6/2011-12 आदेश दिनांक 21.01.2013 से परिवर्तित होकर, विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा म.प्र. द्वारा रा.प्र. क्रं. 88:अ-06/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2011 को स्थिर रखी हुए पुष्टि किए जाने हेतु निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पर यह रिवीजन प्रस्तुत है कि :-



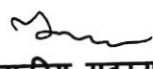
25 SEP 2017

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4315

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/3/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरुद्ध दिनांक 25.09.2017 को लगभग एक वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दी गई। जून-2017 में आवेदक को अपने अधिवक्ता से जानकारी लेने पर पता चला कि दिनांक 27.09.2017 को आदेश पारित हो चुका है, इसके उपरांत उन्हें दिनांक 14.07.2017 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई। उसके उपरांत यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 25.09.2017 को प्रस्तुत की गई है जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में है। आवेदक द्वारा विलंब क्षमा करने के संबंध में दिया गया उक्त तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा इस संबंध में अधिवक्ता का कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त उनको 14.07.2017 को नकल प्राप्त होने के दो माह से भी अधिक समय उपरांत निगरानी पेश की गई है, इस विलंब का भी कोई समुचित एवं समाधानकारक कारण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	